केंद्रीय सहायता के वितरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानदंड में भारांश के माध्यम से तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से, इस संबंध में राज्यों की सहायता करता हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Proposal for making Visakhapatnam as Export Promotion Zone

2121. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Visakhapatanam is proposed to be made an export promotion zone having latest infrastructual facilities;

(b) if so, the details thereof with background including amount involved in such initiatives;

(c) whether the Central Government propose to share the funds of the project;

(d) if so, the details thereof and if not the reasons therefor;

(e) whether Government propose to ask other State Government of coastal areas to take up similar projects like the one undertaken by Andhra Pradesh Government; and

(f) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (f) The Export Processing Zone set up by the Central Govt, at Visakhapatnam is operational since 1.4.1993. Basic infrastructure facilities in the first phase covering an area of 163 acres have been completed. The expenditure so far incurred is Rs. 15.92 crores. In accordance with the practice, the expenditure in respect of provision of infrastructure within the Zone is entirely met by the Central Government. Keeping in view the availability of funds and the need to optimise the infrastructural facilities in the existing Export Processing Zones, there is no proposal at present for the Central Government to set up new Zones in the Country. However, Export Processing Zones can now also be established by the State Governments or in the joint/private sectors after obtaining the approval of the Government of India.

कृषि मजदूरों की संख्या

2122. **श्री नागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री 7 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 855 के दिए गए उत्तर को दखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) कृषि मजदूरों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी हैं; और

(ख) इन मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (**श्री जी. वेंकट स्वामी**) : (क) एक विवरण संलग्र हैं (नीचे देखिए)।

(ख) समस्या को एक बहुत आयामी कार्रवाई, अर्थात् ग्रामीण अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करके, गैर-फार्म कार्यकलापों के विविधीकरण, कौशल सुधार कार्यक्रमों, स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और भू-संसाधनों आदि का अधिक से अधिक उपयोग करके निपटाने की अपेक्षा की गई हैं। 1993-94 से दो और अधिक महत्वपूर्ण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को, अर्थात् गहन जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) को देश में 120 पिछड़े जिलों में तथा रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) को देश में 2000 पिछड़े और जनजातीय ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि श्रमिकों की संख्या (1991 की जनगणना)
1.	भारत	74,597,744 (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर)
2.	आन्ध्र प्रदेश	11,625,159
3.	असम	844,964
4.	बिहार	9,512,892
5.	गुजरात	3,230,547
6.	हरियाणा	8.92,782
7.	हिमाचल	58,668
8.	जम्मू एवं कश्मीर	-
9.	कर्नाटक	4,999,959
10.	केरल	2,120,452
11.	मध्य प्रदेश	5,863,029
12.	महाराष्ट्र	8,313,223
13.	मणिपुर	47,350
14.	मेघालय	89,492
15.	नागालैंड	7,233
16.	उड़ीसा	2,976,750
17.	पंजाब	1,452,828
18.	राजस्थान	1,391,670
19.	सिक्किम	12,851
20.	तमिलनाडु	7,896,295
21.	त्रिपुरा	187,538
22.	उत्तर प्रदेश	7,833,258
23.	पश्चिम बंगाल	5,055,478
24.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	4,989
25.	अरूणाचल प्रदेश	20,054
26.	चंडीगढ़	1,642
27.	दादर एवं नागर हवेली	6,233
28.	दिल्ली	25,195
29.	गोवा	35,284
30.	दमन एवं दीव	1,199
31.	लक्षद्वीप	-
32.	मिजोरम	9,527
33.	पाणिचेरी	77,203

Method Study of Training Directorate

2123. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to refere to the answer to Unstarred Question 1371 given in the Rajya Sabha on the 14th August, 1995 and state:

(a) whether the tentative reports on Method Study of Training Directorate have since been finalised;